देशबन्धु

# सीआईएबीसी ने छत्तीसगढ़ सरकार को पूर्ण शराबबंदी पर फिर से विचार करने का किया अनुरोध

**नई दिल्ली,** 18 अगस्त (देशबन्धु)। शराब उत्पादक कंपनियों की प्रतिनिधि संस्था सीआईएबीसी (कनफेडरेशन ऑफ इंडियन बेवरेज कम्पनीज) ने छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य में पूर्ण शराबबंदी के अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करें। सीआईएबीसी ने कहा है कि उन्हें यह पता चला है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के लिए चर्चा की जा रही है। ऐसा करने से पहले सरकार उन्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति दें और इसके लिए एक अवसर प्रदान करे। संस्था का कहना है कि शराबबंदी को लेकर हकीकत और मिथ में कितना अंतर है। इसकी पूरी पड़ताल होनी जरूरी है। सीआईएबीसी के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी ने इस संदर्भ में राज्य सरकार को एक विस्तृत पत्र भी लिखा है। जिसमें शराबबंदी को लेकर बिहार की वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पत्र में यह भी बताया गया है कि देश में सबसे पहले शराबबंदी करने वाले गुजरात राज्य ने भी हकीकत को स्वीकार करते हुए राज्य में पर्यटकों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए शराब के सेवन का नियम लागू किया। इसी तरह से हरियाणा, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों ने शराबबंदी का नियम लागू करने के बाद उसे वापस किया। पत्र में यह भी कहा गया है कि यह भी एक मिथ है कि शराबबंदी के नारे के साथ ही कोई भी दल सत्ता में आ सकता है।